

प्रश्नक.

पी०के० महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पी०के०।

ग्राम्य विकास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 14 अगस्त, 2007

विषय:- 12.वां वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा संस्तुत अनुदान की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 3046/5 बजट/आयोजनेत्तर/2006-07 दिनांक 15-12-2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत की गई धनराशि में से विकास खण्ड धौलादेवी के आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार हेतु आर०ई०एस० द्वारा गठित आगणन परीक्षणोपरान्त रु० 51.85 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने एवं वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 51.85 (इक्यावन लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
3. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जायें।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टैकअप किया जायें।
6. कार्य करने में पूर्ण सम्पन्न औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों का ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूमी-मापि निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जायें।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये एवं मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायें।
9. निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा कर सापेक्ष उपयुक्त पायी जान वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जायें।
10. जी०पी०डब्ल्यू० काम 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समग्र से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 2047XIV-219/(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय नियमों व कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13. उक्त धनराशि का व्यय 31-3-2008 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान सं० -07 के लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य -80-सामान्य-053-रख-रखाव तथा मरम्मत (आयोजनेत्तर)-01-केंद्रीय आयोजनागत /केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0101-12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

14 यह आदेश वित्त विभाग के असा० संख्या 5(एन०पी०) वित्त अनु०-4/2006 दिनांक 8 अगस्त, 2007 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(पी०के० महान्ति)

सचिव

संख्या 508(1)/XI/06/56(10)/06 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
- 3- जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
- 4- अपर सचिव, वित्त 12वां वित्त आयोग वित्त आयोग निदेशालय देहरादून।
- 5- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-
- 7- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा देहरादून।
- 9- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अल्मोड़ा।
- 10- एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)

अपर सचिव